[Shri Hari Vishnu Kamath]

putting it to the vote, even the motion for consideration of the Bill, because that would not be in order according to the rules of the House unless there is at least two-thirds majority of the members present in the House as well as a simple majority of the total membership. And that being impossible today, on the strength of the assurance given by the Minister, who is not known for breach of promise, convinced and hoping, not against hope, but keenly hoping that Government would bring a Bill on these lines in the next session, budget session itself, or at the latest during the next year, 1966, I would seek leave of the House to withdraw the measure at this stage.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Bill.

Some hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

16.59 hrs.

ALL INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

—(INSERTION OF NEW SECTION 3A)

by Shri C. K. Bhattacharyya—contd.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the All-India Services Act, 1951, be taken into consideration."

While moving this Bill, I want to give a brief summary.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue his speech the next day.

16.59½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-SECOND REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Forty-Second Report of the Business Advisory Committee.

---

17 hrs.

*REPAYMENT OF LOAN BY TISCO AND IISCO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, टिस्को और इस्को को सरकार के द्वारा ग्यारह, बारह साल पहले जो विशेष कर्जा दिया गया था उस के बारे में मैं यह बहस उठाना चाहता हूं । इस पर इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं और उन के जवाब भी आ चुके हैं । लेकिन मेरा खयाल है कि सरकार का जो रवैया इधर दस बारह सालों से रहा है उस से सदन के किसी भी सदस्य को सन्तोष नहीं है । खुद इस्पात मंत्री ने पिछली मर्तबे इस कर्जे की बात को लेकर यह बात कही थी कि यह बड़ी दुखी कहानी है । इस सदन के अधिक से अधिक सदस्यों की यह राय है कि यह केवल दुखी नहीं है बल्कि शर्मनाक है । इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जहां तक बड़े पूंजीपतियों का सवाल है सरकार का रुख उनके बारे में सख्ती का नहीं रहा है । अगर सख्ती का रुख रहा होता तो इस के बारे में कोई दूसरे कदम अवश्य उठाये जाते ।

अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो करार किया गया और 10 करोड़ रु० टाटा के इस्पात कारखाने को दिये गये और 10 करोड़ रु० बीरेन मुकर्जी के कारखाने को दिये गये, और बाद में 18 लाख रु०

---

*Half-an-hour Discussion.